(1975) 2 SCR 449

अधीर नाइया

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य

16 अक्टूबर, 1974

[वाई. वी. चंद्रचूड़ और आर. एस. सरकारिया, जे. जे.]

भारत का संविधान, धारा 32 - बंदी प्रत्यक्षीकरण- एकल एकाकी घटना के आधार पर निरोध- आधार की पर्याप्तता क्या न्यायसंगत - क्या अपील की अदालत यदि कोई उचित व्यक्ति निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है-पिछले आचरण से उत्पन्न होने वाले भविष्य के बारे में आशंका।

याचिकाकर्ता को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के तहत इस आधार पर हिरासत में लिया गया था कि एक विशेष दिन पर उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खाद्यान्न से भरी एक रेलवे वैगन को तोड़ दिया। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में तर्क दिया कि उन्हें एकल घटना के आधार पर हिरासत में लिया गया था और कोई भी उचित व्यक्ति संभवतः इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकता था कि याचिकाकर्ता को समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और

सेवाओं के रखरखाव के प्रतिकूल व्यवहार करने के लिए उसे हिरासत में लेना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि निरोध के आधारों की पर्याप्तता एक न्यायोचित मुद्दा नहीं है और अदालतें केवल इस बात पर विचार कर सकती हैं कि क्या निरोध के आधार उन आधारों के अनुरूप हैं जिनके आधार पर निरोध का आदेश दिया गया है। यदि खाद्य पदार्थों की चोरी करने के उद्देश्य से गाड़ी तोड़ना समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के साथ संबंध रखता है, तो हिरासत को सभी घटनाओं में बरकरार रखा जाना चाहिए और अदालतों को इस सवाल में प्रवेश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि क्या कोई अन्य निष्कर्ष हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के समक्ष रखे गए तथ्यों के आधार पर संभव था।

नजरबंदी को दरकिनार करते हुए, अभिनिर्धारित- देबू महतो बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1974-4 एस.सी.सी.135) में इस न्यायालय के निर्णय के बाद, यह सच है कि अदालतें निरोध आदेश के औचित्य पर अपील में नहीं बैठ सकती हैं। लेकिन निरोध की आवश्यकता वाले आधारों की पर्याप्तता के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता और यह जांचने के लिए कि क्या कोई उचित व्यक्ति इस धारणा तक पहुंच सकता है कि जब तक किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाता है, वह संभवतः इसी तरह के

आचरण में लिप्त होगा, को जाँचने की अधिकारिता के बीच एक अंतर है। जब तक निरोध के आधार निरोध के उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं, तब तक अदालतें निरोध प्राधिकारी के समक्ष रखे गए आंकड़ों के साक्ष्य मूल्य का मूल्यांकन नहीं करती। वर्तमान मामले में, कोई भी उचित व्यक्ति वैगन तोड़ने के एकल कार्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है कि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेना आवश्यक है। याचिकाकर्ता पर आरोपित कृत्य की प्रकृति और उसके संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, न केवल इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निरोध का आधार एकल घटना को संदर्भित करता है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह संतोष पूर्वक मान लेना कि याचिकाकर्ता को जब तक हिरासत में नहीं लिया जाता है, भविष्य में इसी तरह के कृत्य करने की संभावना है, ऐसा निर्णय है जिस पर कोई भी उचित व्यक्ति संभवतः नहीं पहुंच सकता है। यह निष्कर्ष कि अतीत का आचरण बंदी के भविष्य के व्यवहार के बारे में आशंका पैदा करता है, कम से कम तर्कसंगत होना चाहिए। [452 ए-बी. डी.]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: रिट याचिका संख्या 254/1974 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका।

याचिकाकर्ता की ओर से एस के गंभीर।

प्रतिवादी की ओर से पीके चटर्जी और जीएस चटर्जी।

न्यायालय का निर्णय चंद्रचूड, जे द्वारा दिया गया था -

29 मई, 1972 के एक आदेश द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट, 24 परगना ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम, 1971, के तहत हिरासत में लिया जाए क्योंकि वह समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं कि व्यवस्था के विपरीत तरीके से कार्य कर रहा था। हिरासत के आधार का विवरण इस प्रकार वर्णित एकल घटना को संदर्भित करता है:

"कि 24-5-72 को लगभग 10.35 बजे आपने अपने सहयोगियों के साथ मथुरापुर गुड्स साइडिंग पर खाद्यान्न से लदे बीईएक्स वैगन संख्या डब्लू आर 75961 को तोड़ दिया और गेहूं और चावल के 10/12 थैले लेकर भाग गए। आपकी कार्रवाई से आपूर्ति और सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ है।"

इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में जारी नियम प्रतिवादी, पश्चिम बंगाल राज्य को दिए जाने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने याचिका के जवाब में एक जवाबी हलफनामा दायर किया। उपरोक्त हलफनामे के पैराग्राफ 5 में कहा गया है कि हिरासत का आदेश जिला मजिस्ट्रेट के संतुष्ट होने के बाद पारित किया गया था कि याचिकाकर्ता को समुदाय की आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेना आवश्यक था। कि जिला मजिस्ट्रेट इस बात

से संतुष्ट थे कि यदि याचिकाकर्ता को हिरासत में नहीं लिया गया तो वह ऊपर वर्णित तरीके से कार्य कर सकता है; और यह कि: "कार्य की प्रकृति, जिस तरह से यह किया गया था, समुदाय पर उक्त गतिविधि का प्रभाव और परिणाम और खाद्यान्न की आपूर्ति के सवाल पर नजरबंदी का आदेश देने से पहले मेरे द्वारा विचार किया गया था"।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता को एक एकल, पृथक घटना के आधार पर हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था और कोई भी उचित व्यक्ति संभवतः इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका कि याचिकाकर्ता को समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के विपरीत कार्य करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेना आवश्यक था। हमारी राय में, यह निवेदन उचित है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। देबू महतो बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1974-4-एससीसी-135), में जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित कर निर्देश दिया था कि उसमें याचिकाकर्ता को समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाए। हिरासत का केवल एक ही आधार निर्धारित किया गया था, अर्थात्, याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों ने रेलवे वैगन को तोड़ने के बाद जूट की खाली बोरियों की तीन गांठें हटाते हुए पाया गया था और जब रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चुनौती दी गई तो वे लूट

का माल छोड़कर भाग गए। तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने माना कि यद्यपि यह एक अपरिवर्तनीय नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि किसी भी मामले में एक एकल, एकमात्र कार्य इस संतुष्टि तक पहुंचने का आधार नहीं बन सकता है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में ऐसे कार्य दोहरा सकता है। कतिपय मामले की परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा किया गया वैगन तोड़ने का एक अकेला कृत्य संभवतः किसी भी उचित व्यक्ति को इस संतुष्टि तक पहुंचने के लिए राजी नहीं कर सकता कि जब तक याचिकाकर्ता को हिरासत में नहीं लिया गया, वह पूरी संभावना है कि वह वैगन तोड़ने के अन्य कृत्यों में शामिल होगा। न्यायालय इस निष्कर्ष पर इस आधार पर नहीं पहुंचा कि जो चोरी हुआ था वह खाली जूट-बैग थे। निष्कर्ष इस परिस्थिति पर आधारित है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जो आरोप लगाया गया था वह वैगन तोड़ने के एक अकेले, एकांकी कार्य में उसकी संलिप्तता थी और दूसरी बात, जिला मजिस्ट्रेट ने अपने जवाबी हलफनामे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिससे यह पता चलता हो कि वैगन तोड़ना इतना बड़े पैमाने पर हो गया था कि विचित्र स्थिति के संदर्भ में, जिला मजिस्ट्रेट इस तथ्य के बावजूद अपेक्षित संतुष्टि पर पहुंचे कि जिस कार्य पर संतुष्टि आधारित थी वह वैगन तोड़ने का सिर्फ एक एकल, एकांकी कार्य था। किसी भी दो मामलों में सटीक रूप से समान तथ्य नहीं हो सकते हैं लेकिन हम अपने सामने वाले मामले के तथ्यों और देबू महतो के मामले के तथ्यों में

कोई तात्विक अंतर देखने में असमर्थ हैं। याचिकाकर्ता को एक ही कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और इसमें एक वैगन को तोड़कर गेहूं और चावल के 10 या 12 बैग की चोरी शामिल है। इस कृत्य के साथ हिंसा या बल का प्रदर्शन नहीं किया गया था और जिला मजिस्ट्रेट ने अपने हलफनामे में यह नहीं कहा है कि स्थिति की विचित्रता या गंभीरता के कारण, उन्होंने याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने की आवश्यकता के संबंध में अपेक्षित संतुष्टि का बोध हुआ, भले ही संतुष्टि का आधार एक एकाँकी घटना थी।

पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश होने वाले श्री चटर्जी का तर्क है कि देबू महतो के मामले में इस न्यायालय का निर्णय मुख्य रूप से इस विचार से प्रभावित था कि जिला मजिस्ट्रेट ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि याचिकाकर्ता "एक कुख्यात वैगन ब्रेकर" था और रेलवे-वैगनों को व्यवस्थित रूप से तोड़ने में लगा हुआ था। हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं।देबू महतो के मामले में हिरासत आदेश को अमान्य करने के लिए दो आधारों का आग्रह किया गया था। पहला 'आधार यह था कि जिला मजिस्ट्रेट संभवतः एकल घटना के आधार पर इस संतुष्टि तक नहीं पहुंच सकते थे कि जब तक याचिकाकर्ता को हिरासत में नहीं लिया जाएगा, वह वैगन-ब्रेकिंग के आगे के कृत्यों में शामिल होगा। इस तर्क पर विचार करते समय, न्यायालय द्वारा इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं दिया गया कि जवाबी

हलफनामे में, जिला मजिस्ट्रेट ने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया था जिनके बारे में बंदी को नहीं बताया गया था। यह मानते हुए कि आदेश को इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि वास्तव में बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं थी, न्यायालय ने हमले के दूसरे आधार पर विचार किया, अर्थात्, हिरासत का आदेश जिन तथ्यों पर आधारित था याचिकाकर्ता को नहीं बताया गया। इसीलिए हमले के दूसरे आधार पर निर्णय यह कहते हुए शुरू होता है: "एक और कोण भी था जिससे याचिकाकर्ता की ओर से हिरासत के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी"। निर्णय से यह स्पष्ट है कि हिरासत के आदेश को दो अलग-अलग और विशिष्ट आधारों पर बुरा माना गया था और जिन कारणों से मामले के दूसरे पहलू पर न्यायालय ने विचार किया, उन्होंने हमले के पहले आधार पर उसके निर्णय को प्रभावित नहीं किया।

राज्य के वकील ने तब आग्रह किया कि हिरासत के आधारों की पर्याप्तता एक न्यायसंगत मुद्दा नहीं है और अदालतें इस बात पर विचार कर सकती हैं कि क्या हिरासत के आधार उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं जिसके लिए हिरासत का आदेश दिया गया है। विद्वान वकील का तर्क है कि यदि खाद्य पदार्थों की चोरी करने के उद्देश्य से वैगन-लूटने का संबंध समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के साथ संबंध है, तो हिरासत को हर सूरत में बरकरार रखा जाना चाहिए और न्यायालयों के

पास इस सवाल पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि क्या कोई निरूद्ध प्राधिकारी के समक्ष रखे गये तथ्यों के आधार पर अन्य निष्कर्ष सम्भव हो सकता था। यह सच है कि अदालतें हिरासत के आदेशों के औचित्य पर अपील की सुनवाई नहीं कर सकतीं। लेकिन राज्य का तर्क हिरासत की आवश्यकता वाले आधारों की पर्याप्तता जांचने के लिए न्यायालय के क्षेत्राधिकार और उसका वो क्षेत्राधिकार जो यह जांच करे कि क्या एक उचित व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि जब तक व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाता है, तब तक पूरी संभावना की वह उसी तरह का आचरण करे, के बीच अंतर को नजरअंदाज कर देता है। हमें इस बात पर विचार करने की चिंता नहीं है कि क्या जिला मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर हिरासत का आदेश पारित करना उचित था। जब तक हिरासत के आधार हिरासत के उद्देश्य के अनुरूप हैं, तब तक अदालतें हिरासत के आदेश को उचित ठहराने के लिए उस डेटा की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखे गए डेटा के साक्ष्य मूल्य को नहीं तौलती हैं। मामले का मुद्दा यह है कि याचिकाकर्ता को जिस कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है उसकी प्रकृति और उसके संदर्भ पर विचार करते हुए, न कि केवल इस तथ्य पर कि हिरासत का आधार एक ही घटना को संदर्भित करता है, जिला मजिस्ट्रेट की इस बात से संतुष्टि कि याचिकाकर्ता, जब तक हिरासत में नहीं लिया जाता है, उसके भविष्य में इसी तरह के कृत्य करने की

संभावना थी, ऐसा है कि जिस तक कोई भी उचित व्यक्ति संभवतः नहीं पहुंच सकता था। यह निष्कर्ष कि बंदी का पिछला आचरण उसके भविष्य के व्यवहार के बारे में आशंका पैदा करता है, कम से कम तर्कसंगत होना चाहिए।

तदनुसार, हम निरोध के आदेश को दरकिनार करते हैं, इस याचिका में नियम को पूर्ण बनाते हैं और निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

पीएच.पी. याचिका की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।